भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
06.08.2025 के
तारांकित प्रश्न सं. 249 का उत्तर

गुजरात में रेल परियोजनाएँ

***249. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में चल रही/लंबित/प्रस्तावित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आवासीय क्षेत्रों और हरियाली को नुकसान न पहुँचाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है कि इन परियोजनाओं से गुजरात के पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ग) गुजरात में मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति और उसकी भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजकोट में मेट्रो रेल शुरू करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का माल ढुलाई यातायात के लिए एलिवेटेड रेल लाइनें बिछाने और कृषि भूमि के अधिग्रहण से बचने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 06.08.2025 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 249 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, न कि राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार/जिला-वार, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/जिलों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमान, अंतिम छोर तक संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं की देयताओं और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

गुजरात राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के पश्चिम रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे ज़ोनों के अंतर्गत आती हैं। रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार विवरण भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाता है।

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 30,275 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 2564 किलोमीटर लंबाई की 36 रेल परियोजनाओं (06 नई लाइन, 17 आमान परिवर्तन और 13 दोहरीकरण) को स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 863 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2025 तक 12,865 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। विवरण निम्नानुसार है:-

कोटि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 25 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2025 तक कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	6	532	105	5494
आमान परिवर्तन	17	1379	718	6213
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	13	653	40	1158
कुल	36	2564	863	12865

गुजरात राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं एवं संरक्षा कार्यों हेतु बजट आबंटन निम्नानुसार हैं:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	589 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2025-26	17,155 करोड़ रु. (29 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और 2014-25 के दौरान गुजरात राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाले नए रेलपथ को कमीशन करने/बिछाने का विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	660 कि.मी.	132 कि.मी. प्रति वर्ष
2014-25	2764 कि.मी.	251 कि.मी. प्रति वर्ष (लगभग 2 गुना)

गुजरात राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम लागत (करोड़ रुपए में)
1.	भीलडी-विरमगाम आमान परिवर्तन (156 कि.मी)	312
2.	केवडिया आमान परिवर्तन (50 किलोमीटर) तक विस्तार के साथ दाभोई-चंदोद	1018
3.	अहमदाबाद-बोटाड आमान परिवर्तन (170 कि.मी)	1810
4.	ढासा-जेतलसर आमान परिवर्तन (104 कि.मी)	1024
5.	अहमदाबाद-मेहसाणा आमान परिवर्तन (69 कि.मी)	874
6.	काटोसन रोड-चानसामा आमान परिवर्तन (38 कि.मी)	484
7.	कलोल-कादी-काटोसन आमान परिवर्तन (37 कि.मी)	347
8.	वीरमग्राम-सुरेंद्रनगर दोहरीकरण (65 कि.मी)	382
9.	उधना-जलगांव दोहरीकरण (307 किलोमीटर)	2448
10.	गुरिया-मारवाड़ और करजोदा-पालनपुर दोहरीकरण (49 कि.मी)	251
11.	आबू रोड से सरोत्रा रोड दोहरीकरण (24 कि.मी)	152
12.	सरोत्रा रोड - करजोदा दोहरीकरण (24 कि.मी)	220
13.	विरमगाम-समख्याली दोहरीकरण (182 कि.मी)	1492
14.	पालनपुर-समख्याली दोहरीकरण (247 कि.मी.)	2538

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम लागत (करोड़ रुपए में)
15.	मेहसाणा-पालनपुर दोहरीकरण (65 कि.मी)	537
16.	सुरेंद्रनगर-राजकोट दोहरीकरण (116 कि.मी)	1425
17.	आनंद-गोधरा दोहरीकरण (79 कि.मी)	692
18.	स्वचालित सिगनल प्रणाली के साथ वटवा-अहमदाबाद तीसरी लाइन (8 कि.मी)	61

गुजरात राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाली शुरू की गई कुछ मुख्य परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1.	नलिया-जखाउ पोर्ट नई लाइन (25 किमी)	410
2.	मियागाम-कर्जन-चोरंदा-मालसर आमान परिवर्तन (37 किमी)	450
3.	जंबुसर-कावि आमान परिवर्तन (26 किमी)	318
4.	कोसंबा-उमरपाड़ा आमान परिवर्तन (70 किमी)	468
5.	खिजड़िया-अमरेली आमान परिवर्तन (17 किमी)	178
6.	गांधीधाम (जीआईएम) - आदिपुर (एआई) चौहरीकरण (11 किमी)	152
7.	बरेजदी-नांदेज (गेरातपुर)- साणंद चौथी लाइन (38 किमी)	962
8.	समख्याली और गांधीधाम चौहरीकरण (53 किमी)	1430
9.	विश्वामित्री-दाभोई सहित विश्वामित्री दोहरीकरण पर 'वाई' कनेक्शन (33 किमी)	394
10.	लूनी-समदड़ी-भीलड़ी दोहरीकरण (272 किमी)	3086
11.	साबरमती डी केबिन-सरखेज दोहरीकरण (21 किमी)	323

पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) भी गुजरात से होकर गुजरता है। पश्चिमी डीएफसी का लगभग 565 किलोमीटर मार्ग गुजरात में स्थित है, जो पश्चिमी डीएफसी की कुल मार्ग लंबाई का लगभग 37% है। गुजरात राज्य में पड़ने वाली पूरी परियोजना का निर्माण कार्य कमीशन किया गया है।

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना (508 किलोमीटर) को जापान सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से निष्पादित किया जा रहा है। गुजरात में फ्लैगशिप हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब, 100% भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जा चुका है। गुजरात राज्य में पड़ने वाली इस परियोजना के 352 किलोमीटर (नींव कार्य और खंभों) खंड के लिए वायाडक्ट का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके साथ ही, 329 किलोमीटर गर्डर कास्टिंग और 309 किलोमीटर गर्डर लॉन्चिंग का कार्य भी पूरा किया जा चुका है।

पिछले 3 वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) और चालू वित्त वर्ष के दौरान, गुजरात राज्य में पूर्णतः/अंशत: पड़ने वाले कुल 6,321 किलोमीटर लंबाई के 58 सर्वेक्षण कार्यों को स्वीकृत किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण सर्वेक्षण कार्य निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लंबाई (कि.मी. में)
1	रतलाम-वडोदरा तीसरी और चौथी लाइन	259
2	विरमगाम-कनालूस चौहरीकरण	293
3	कनालूस-ओखा दोहरीकरण	141

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार होने के पश्चात, परियोजना की मंजूरी के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और आवश्यक अनुमोदन जैसे नीति आयोग, वित्त मंत्रालय आदि से मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। चूंकि परियोजनाओं को मंजूरी देना सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए सटीक समय-सीमा तय नहीं की जा सकती।

प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारंभ होने से अवसंरचनात्मक परिवहन परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में परिवर्तनकारी दृष्टिकोण आया है। देश भर में फैले नेशनल मास्टर प्लान से संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों/विभागों के बीच आपसी सहयोग से रेलवे, जहाजरानी, सड़क मार्ग, दूरसंचार, पाइपलाइन आदि जैसे अवसंरचनात्मक क्षेत्रों के बीच तालमेल स्थापित हुआ है, जिससे परिवहन दक्षता, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, परिणामस्वरूप परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक स्वीकृतियों के साथ-साथ योजना तैयार करने में तेजी आई है।

सड़क परिवहन की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन, ऊर्जा दक्षता और संकुलन कम होने के कारण रेल परिवहन स्वाभाविक रूप से अधिक पर्यावरण अनुकूल है। रेल परिवहन की लागत न केवल सड़क परिवहन की तुलना में आधे से भी कम है, बल्कि इसका कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी सड़क परिवहन की तुलना में 90 प्रतिशत कम है। यातायात को सड़क से रेल पर स्थानांतरित करने से भारत को बड़े पैमाने पर अपनी अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने में मदद मिल रही है। वर्ष 2014 के स्तर की तुलना में, सड़क से रेल पर 26,782 मीट्रिक टन अधिक माल ढुलाई को स्थानांतरित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 143.3 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। यह अपने आप में 100 करोड़ वृक्षों के समतुल्य है।

अभी तक लगभग 99% बड़ी लाइन (बीजी) रेल नेटवर्क को विद्युतीकृत किया जा चुका है। वर्ष 2014-25 के दौरान और 2014 से पहले किए गए विद्युतीकरण कार्य का विवरण निम्नानुसार है:

अवधि	मार्ग किलोमीटर
2014 से पूर्व (लगभग 60 वर्ष)	21,801
2014-25	46,900

गुजरात राज्य में, मौजूदा बड़ी लाइन रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण कर दिया गया है। सभी नई लाइन/मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को विद्युतीकरण के साथ स्वीकृत और निर्मित किया जा रहा है।

शहरी परिवहन, जो शहरी विकास का एक अभिन्न अंग है, राज्य से संबंधित विषय है। मेट्रो रेल परियोजनाओं सहित शहरी परिवहन अवसंरचना को शुरू करने और विकसित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश (यूटी) उत्तरदायी हैं। गुजरात राज्य में मेट्रो रेल परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की लंबाई (कि.मी. में)	परिचालनिक लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)
1	अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण I	40	40	10,773
2	अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण II	28	23	5384
3	सूरत मेट्रो रेल परियोजना	40	-	12,020

गुजरात सरकार ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को 41 किलोमीटर लंबी राजकोट मेट्रो रेल परियोजना, जिसकी कुल अनुमानित लागत 10,427 करोड़ रूपए है, को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मेट्रो परियोजना की अत्यधिक लागत के कारण, इसके लिए विभिन्न स्तरों पर व्यापक मूल्यांकन और जाँच की आवश्यकता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए निधि आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल हैं। इनके परिणामस्वरूप, 2014 से कमीशनिंग की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

किसी भी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकारों द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति देने, अतिलंघनकारी उपयोगिताओं को स्थानांतरित करना, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी प्राप्त करना, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियों, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना विशेष स्थलों के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

*****